गुजरात में वन परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक से वित्तीय सहायता

1823. **श्री हीरा लाल आर० परमार :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्व बैंक, गुजरात में वन परियोजना के लिये भारत को वित्तीय सहायता दे रहा है, यदि हां, तो सहायता किस रूप में दी जानी है और सहायता की कुल राशि कितनी है; और

(ख) क्या ये वित्तीय सहायता किन्हीं विशेष शर्तों पर दी जा रही है और यदि हां, तो इन शर्तों की रूपरेखा क्या है और सहायता कब तक प्राप्त होगी ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन): (क) जी, हां । विश्व बैंक गुजरात सामुदायिक वानिकी परियोजना को वित्तीय सहायता दे रहा है । 760 लाख अमरीकी डालर की कुल लागत वाली इस परियोजना का 48 प्रतिशत भाग (अर्थात् 370 लाख डालर) विश्व बैंक द्वारा 1979-80 से 5 वर्षों की अवधि में किस्तों के रूप में दिया जाएगा ।

(ख) विश्व बैंक के साथ किए गए करार के अनुसार ऋण की मुख्य शर्तें निम्नलिखित हैं :—

1. करार में उल्लेख न की गई किसी भी मद के खर्च के लिए ऋण से धन नहीं दिया जाएगा ।

2. ऋण की अदायगी की अन्तिम तारीख 31 दिसम्बर, 1985 अथवा विश्व बैंक द्वारा निर्धारित तारीख होगी । भारत सरकार संघ को ऋण की धनराशि के 1 प्रतिशत वार्षिक का 3/4 भाग सेवा प्रभार के तौर पर अदा करेगी ।

3. भारत सरकार ऋण की धनराशि को प्रतिवर्ष दो किश्तों में वापस करेगी जो 15 अप्रैल, 1990 से आरम्भ होगी तथा 15 अक्तूबर, 2029 को समाप्त होगी ।

4. विभिन्न प्रकार की वे मदें जिन के लिये ऋण की राशि से धन प्राप्त होगा, प्रत्येक श्रेणी के लिये धन का आवंटन तथा प्रत्येक मद से संबंधित व्यय की प्रतिशतता निम्नलिखित प्रकार होगी :—

श्रेणी	आवंटित ऋण की धनराशि डालर के समतुल्य	उन खर्चों की प्रतिशतता जिन के लिए धन दिया जाना है
1	2	3
		प्रतिशत
क. सिविल निर्माण कार्य	2,300,000	55
ख. उपस्कर तथा वाहन	2,900,000	विदेशी व्यय 100 प्रतिशत तथा स्थानीय व्यय का 70 प्रतिशत
ग. प्रत्यक्ष वन-रोपण का व्यय	21,400,000	55
घ. स्टाफ का वेतन	7,900,000	55
ङ. प्रशिक्षण		
(क) स्थानीय 640,000		

1	2	3
(ख) विदेशी		
60,000	700,000	100 प्रतिशत
च. स्टोव तथा क्रिमेटोरीया	300,000	55 प्रतिशत
छ. प्रांवटित	1,500,000	
योग	37,000,000	

5. यह सहायता 1 जून, 1979 से उपलब्ध की गई है

Fact Finding Committee on Indian School Mines

1824. SHRI A. K. ROY: Will the Minister of EDUCATION AND SOCIAL WELFARE be pleased to state:

(a) whether the Fact Finding Committee constituted on the Indian School of Mines, Dhanbad, has submitted its Report; if so main findings of the Committee;

(b) whether the Report would be placed before the Executive Board for scrutiny and action; if so, when; and

(c) if not. reasons therefor?

THE MINISTER OF EDUCATION AND SOCIAL WELFARE (SHRI S. B. CHAVAN): (a) Yes, Sir. The main findings of the Committee are: (i) the various allegations of irregularities/corruptions against the Director are without substance, and (ii) some additional measures should be taken to further improve the administration of the School.

(b) and (c). The report has already been placed before the Executive Board at its meeting held on 16-9-1980. The Executive Board has accepted the report and directed the school to take further necessary action on the recommendations made by the committee.

DDA Flats

1825. SHRI SUSHIL BHATTACHARYA: Will the Minister of WORKS AND HOUSING be pleased to state:

(a) the total number of flats constituted by the Delhi Development Authority during the years 1978-79, 1979-80 and 1980-81;

(b) the number of people benefited;

(c) the number of persons who registered their names;

(d) the number of flats which are going to be constructed very soon; and

(e) the number of persons who will be benefited?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND WORKS AND HOUSING (SHRI BHISHMA NARAIN SINGH): (a) The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

(b) The number of persons given allotment of flats is as under:

1978-79		..	4,692
1979-80		..	4,051
1980-81	(i)	..	3,104
	(ii) Release of additional about 10,000 flats has been announced by the DDA in November, 1980.		

(c) The requisite information is as under:

(i) Second Self Financing Scheme, 1978-79=4,393.

(ii) Third Self Financing Scheme, 1979-80=3,616.

(iii) Registration Scheme of New Pattern, 1979=1,71,131.

(d) The DDA have reported that the construction of about 32,000 flats is in progress.